Statement

Name of the State/Cadre	No. of IAS Officers
1. Andhra Pradesh	224
2. Assam-Meghalaya	120
3. Bihar	248
4. Gujarat	150
5. Haryana	121
6. Himachal Praddesh	69
7. Jammu & Kashmir	72
8. Karnataka	173
9. Kerala	110
10. Madhya Pradesh	261
11. Maharashtra	238
12. Manipur-Tripura	65
13. Nagaland	38
14. Orissa	147
15. Punjab	129
16. Rajasthan	157
17. Sikkim	25
18. Tamil Nadu	204
19. Union Territories	119
20. Uttar Pradesh	362
21. West Bengal	202
Total	3234

Pension to Freedom Fighters in Bihar and U.P.

4393. SHRI RAM SINGH SHAKYA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of freedom fighters who are getting pension in Bihar and U.P. up-to-date;

(b) whether pensions have been withheld in the case of some freedom fighters;

(c) if so, the number of such pensioners and the reasons therefor; and

(d) the time by which their pension is likely to be restored?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) 19,263 and 18,400 in Bihar and U.P. respectively.

(b), (c) and (d). Pensions have been suspended in 202 cases in Bihar and 494 cases in U.P.

Pensions have been suspended on one or the other of the following grounds:—

(i) Applicant is not a genuine freedom fighter;

(ii) Suffering is less than six months.

(iii) Suffering is not in connection with freedom movement.

(iv) Submission of false documentary evidence.

(v) Claim of internment/externment/abscondence is not supported by evidence.

(vi) Annual income from all sources is more than Rs. 5000/-

Opportunity is given to the persons concerned to explain their position and adduce additional evidence in support of their claim. Their replies are got re-verified through the State Government. Depending on the report of the State Government pensions are restored in eligible cases without delay.

Supply of Cement to U.P.

4394. SHRI ZAINUL BASHEER: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether during the last three months. letters from Uttar Pradesh Government have been received in which attention of the Central Government was drawn to the cement

supply in the entire Uttar Pradesh in general and in the eastern districts of the State in particular;

(b) the action taken by Government in this regard; and

(c) whether the supply pisiton is satisfactory at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA):

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Against an allocataion of 4,37,600 tonnes of cement made for the quarter April-June, 1980, a quantity of 3,84,205 tonnes of cement was despatched to the State of Uttar Pradesh upto 15-6-1980.

सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षकों (आपरटरों) को विशेष वेतन

4395. **श्री दौलत राम सारण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 के नये वेतनमान के अनुसार सीमा सुरक्षा बल के सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटरों) को विशेष वेतन दिया गया था लेकिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को नहीं दिया गया;

(ख) क्या सहायक उप-निरीक्षक आपरेटरो को विशेष वेतन 1974 से 1976 तक दिया गया था लेकिन उसके बाद बन्द कर दिया गया और विशेष वेतन के रूप में उन्हें दी गई राशि उनसे वापस ली गई और क्या जिन रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षक को पहले विशेष वेतन नहीं दिया गया था उन्हें यह विशेष वेतन मिलने लगा और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या आपरेटरों के दो निचले रैंक (नायक, हैड कांस्टेबल) है और दो रैंक (उप-निरीक्षक और निरीक्षक) सहायक उप-निरीक्षको से ऊपर है और क्या ऊंचे और निचले दोनों रैंकों के व्यक्तियो को यह विशेष वेतन मिल रहा है लेकिन वे केवल रेडियो मैकेनिक सहायक उप-निरीक्षकों को ही यह विशेष वेतन नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस असंगति को दूर करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सहायक उप निरीक्षकों (आपरेटरो) को दिया गया विशेष वेतन वाजिब नही पाया गया था । इसलिए सहायक उप-निरीक्षकों को भुगतान किये गये विशेष वेतन की वसूली की गई थी । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) का संशोधित पूर्व वेतनमान (125–155 रु0 माहवार और विशेष वेतन 40 रु0 माहवार) सहायक उप-निरीक्षक रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-।। के वेतनमान (150–320 रु0) से कम था । 1–1–1973 से दोनों श्रेणियों के वेतनमान संशोधित करके समान वेतनमान (330–480 रु0) किया गया । सहायक उपनिरीक्षक (आपरेटर) की तुलना में सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) के हित में कुछ अन्तर रखना वांछनीय समझा गया था । इसलिए सहायक उपनिरीक्षक (रेडियो मैकेनिक) ग्रेड-।। को 1–1–1973 से विशेष वेतन दिया गया था ।

(ग) नायक तथा हैडकांन्सटेबल का पद सहायक उपनिरीक्षक के पद से दो श्रेणी नीचे है और उप निरीक्षक तथा निरीक्षक का पद सहायक उप-निरीक्षक के पद से दो श्रेणी ऊपर है । नायक (संचार) हैड कांस्टेबल (आपरेटर) उप-निरीक्षक (आपरेटर) तथा निरीक्षक (संचार) को विशेष वेतन मिलता है । सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन नही दिया जाता है जैसा कि उपर्यक्त (ख) में स्पष्ट किया गया है सहायक उप-निरीक्षक (आपरेटर) को विशेष वेतन देने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Allegations against Chief Executive of N.I.D.C.

4396. SHRI K. A. RAJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether work load of the National Industrial Development Corporation Ltd. is touching the bottom of the scale whereas other sister consultancy organisations like Engineers India Ltd., MECON etc. have begged prestigious contracts for consultancy assignments both in India and abroad;

(b) whether it is a fact that the Chief Executive of NIDC goes on foreign tours through the auspices of Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and National Associa-